बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

ल.अं./46/एसएलबीसी/सितम्बर 2019/64 **22.01.2019**

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ0 प्र0) के समस्त सदस्यों को पत्र

महोदय/महोदया,

विषय :- राज्य स्तरीय बैकर्स समिति (उ.प्र.) की सितम्बर 2019 हेतु समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

कृपया राज्य स्तरीय बैकर्स समिति (उ. प्र.) की त्रैमासान्त **सितम्बर 2019** को समाप्त तिमाही हेतु आयोजित बैठक दिनांक 30.12.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस क्रम में उपरोक्त बैठक का कार्यवृत्त आपकी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है। हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि संलग्न कार्यवृत्त को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ0 प्र0) की वेबसाइट **www.slbcup.com** पर अपलोड कर दिया गया है।

आपसे अनुरोध है कि कृपया विभिन्न कार्य बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अद्यतन प्रगति हमें प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि तदनुसार आगामी बैठक में इसका समावेश किया जा सके।

भवदीय,

बलबीर सिंह

(बलबीर सिंह लुथरा)
उप महाप्रबन्धक
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ0 प्र0)

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.), अंचल कार्यालय, लखनऊ अंचल, "बड़ौदा हाउस", वी–23, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226 010
State Level Bankers' Committee (U.P.), Zonal Office, Lucknow Zone, "Baroda House", V-23, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226 010
फोन / Phone : 6677607 (GM), 6677609 (Sectt.), 6677722 (DGM), 6677721, 6677694 (DEPTT.)
ई–मेल / E-mail : slbc.up@bankofbaroda.co.in वेबसाइट / Website : www.slbcup.com

राज्य स्तरीय बैकर्स समिति (उ.प्र.) की सितम्बर 2019 तिमाही की दिनांक 30.12.2019 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त

राज्य स्तरीय बैकर्स समिति (उ.प्र.) की सितम्बर 2019 त्रैमास की समीक्षा बैठक दिनांक 30.12.2019 को "5 कालीदास मार्ग, मुख्यमंत्री आवास, लखनऊ" में श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश, श्री सुरेश खन्ना जी, माननीय वित्त मंत्री, उत्तर प्रदेश एवं श्री सूर्य प्रताप शाही जी, माननीय कृषि मंत्री, उत्तर प्रदेश की गरिमामयी उपस्थिति में सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता श्री विक्रमादित्य सिंह खींची, कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा, मुम्बई द्वारा की गयी।

बैठक में श्री अनिल कुमार शर्मा, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक; श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी, मुख्य सचिव; श्री संजीव कुमार मित्तल, अपर मुख्य सचिव संस्थागत वित्त; श्री अवनीश अवस्थी, अपर मुख्य सचिव गृह; श्री आर० लक्ष्मीकांत राव, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ; श्री शिव सिंह यादव, महानिदेशक, संस्थागत वित्त महानिदेशालय, उ0प्र0; श्री जे. एस. उपाध्याय, महाप्रबन्धक, नाबार्ड के साथ ही विभिन्न बैंको/वित्तीय संस्थाओ के वरिष्ठ कार्यपालकों, राज्य व केन्द्र सरकार के उच्चाधिकारियों व मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारीगण ने भी इस बैठक मे सहभागिता की। (सूची संलग्न)

बैठक के प्रारम्भ मे डॉ0 रामजस यादव, महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उ0 प्र0 ने श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश, श्री सुरेश खन्ना जी, माननीय वित्त मंत्री, उत्तर प्रदेश एवं श्री सूर्य प्रताप शाही जी, माननीय कृषि मंत्री, उत्तर प्रदेश का विशेष आभार प्रकट करते हुए सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया। अपने स्वागत सम्बोधन में बैंकों द्वारा प्रदान किए जा रहे सहयोग व कार्यो की सराहना की। उन्होंने प्रदेश में की जा रही बैंकिंग गतिविधियों के साथ-साथ भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे किसान क्रेडिट कार्ड अभियान की अद्यतन प्रगति से सभा को अवगत कराया। इस अवसर पर बैंकों द्वारा स्वीकृत 1.51 लाख किसान क्रेडिट कार्ड्स माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर-कमलों द्वारा कृषकों को समर्पित किये गये।

गत बैठक दिनांक 08.08.2019 के कार्यवृत्त की पुष्टि के उपरांत उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण मानकों पर प्रदेश की स्थिति का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया।

अपने अध्यक्षीय सम्बोधन मे श्री विक्रमादित्य सिंह खींची, कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश; माननीय कृषि मंत्री, उत्तर प्रदेश एवं माननीय कृषि मंत्री, उत्तर प्रदेश का अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकाल कर बैठक में पधारने हेतु विषेश आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही सभा में उपस्थित समस्त सम्मानित सदस्यों का अभिवादन करते हुये देश एवं प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों तथा विभिन्न मानकों में प्रदेश मे हुई प्रगति से सभा को अवगत कराया। उन्होंने राज्य की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने तथा इसे नई ऊंचाइयों तक पहुँचाने मे बैंकों द्वारा प्रदान सहयोग की सराहना करते हुए निम्न बिंदुओं पर प्रकाश डाला:

- चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, सभी बैंकों की जमा राशि मार्च 2019 के सापेक्ष रू 10,12,337 करोड़ के स्तर से बढ़कर सितंबर 2019 में रू 10,52,289 करोड़ हो गयी है जो रू 39952 करोड (3.94%) की वृद्धि दर्शाता है। मार्च 2019 के अग्रिम रू 5,28,188 करोड़ में भी रु 15,103 करोड़ की वृद्धि दर्ज करते हुए सितम्बर 2019 में कुल अग्रिम रू 5,43,291 करोड़ रुपये के स्तर तक पहुँच गया है।

- राज्य मे किसान क्रेडिट कार्ड संतृप्तीकरण अभियान के अंतर्गत बैंकों द्वारा एक दिन में 1.51लाख के.सी.सी. निर्गत करने पर उन्होंने बैंकों की सराहना करते हुए प्रदेश सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष हेतु निर्धारित 25 लाख नये के.सी.सी. जारी करने के लक्ष्य को फरवरी माह तक प्राप्त करने का आह्वाहन किया।

(कार्यवाही: समस्त बैंक)

- प्रदेश का ऋण जमानुपात (CD Ratio) सितम्बर 2019 में समाप्त तिमाही तक 51.63% के स्तर पर रहा जिसमें वृद्धि करते हुए राष्ट्रीय औसत (78%) तक पहुँचाने हेतु समस्त हितधारकों द्वारा सघन प्रयास करने की आवश्यकता पर बल दिया।

- उत्तर प्रदेश में बैंकिंग आउटलेट्स का एक बड़ा नेटवर्क है जिसमें 18,904 बैंक शाखाएँ (जो देश की कुल शाखाओं का 12.38% हैं), 18,034 ATMs एवं 44,297 बी.सी. (BCs) शामिल हैं। वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 166 गांवों की पहचान की गयी जिसमे पर्याप्त बैंकिंग सुविधाएँ उपलब्ध नही थी। उन्होंने अवगत कराया कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सभी केन्द्रो पर 5 किलोमीटर के दायरे में बैंक शाखाओं और बी.सी. द्वारा समस्त बैंकिंग सुविधाएँ उपलब्ध करायी जा रही है।

- वित्तीय समावेशन अभियान के अंतर्गत बैंकों द्वारा सितम्बर 2019 तक PMJDY के अंतर्गत 5.94 करोड़ खातों के साथ प्रदेश पैन इंडिया प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत हमारा प्रदेश पूरे भारत वर्ष में क्रमश: प्रथम एवं द्वितीय स्थान पर है। मुझे यह अवगत कराते हुए हर्ष हो रहा है कि PFRDA द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अधिकतम नामांकन करने हेतु एस.एल.बी.सी. (उ.प्र.) को देश में सर्वश्रेष्ठ एसएलबीसी से सम्मानित किया गया है।

- प्रदेश में -2- जनपद यथा सिद्धार्थनगर (सम्भावनाशील जनपद) और फिरोजाबाद, जहाँ पर भारतीय स्टेट बैंक अग्रणी बैंक की भूमिका का निर्वहन कर रहा है, को एक वर्ष के भीतर डिजिटल भुगतान के साधनों का विस्तार करने के लिए चिन्हित (adopt) किया गया है। सभी बैंकों से अनुरोध है कि भारतीय रिजर्व बैंक के वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन जनपदों में आवश्यक सहयोग प्रदान करें।

(कार्यवाही: समस्त बैंक)

- प्रधानमंत्री मुद्रा योजनांतर्गत प्रदेश द्वारा गत 3 वर्षों से निरंतर लक्ष्यों की शत प्रतिशत प्राप्ति पर सभी बैंकों की सराहना करते हुए बताया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में सितम्बर 2019 तक कुल 25.08 लाख खातों में रू. 11995.63 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है। मैं योजना के तहत बैंकों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करता हूँ और आशा करता हूँ कि चालू वित्तीय वर्ष में भी पूरे उत्साह के साथ काम करेंगे।

- अंतिम व्यक्ति तक ऋण सुविधा पहुँचाने के उद्देश्य से प्रदेश के कुल 46 जनपदों में 2 चरणों में प्रदेश के समस्त बैंको के समंवय व प्रदेश सरकार के सहयोग से "ग्राहक सम्पर्क कार्यक्रम (Customer Outreach Programme) अक्टूबर 2019 माह में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान 65 हज़ार से अधिक खातों में लगभग रू 3000 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया। इन आयोजनों में सभी स्टेकहोल्डर्स द्वारा सक्रिय सहभागिता की गयी। केन्द्र एवं राज्य सरकार के माननीय मंत्रीगणों एवं विशिष्ठ अतिथियों द्वारा अपनी गरिमामयी उपस्थिति से उक्त कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई गयी।

- बैंक बकायों की वसूली हेतु राज्य सरकार के द्वारा दिए जा रहे सहयोग की सराहना करते हुए अवगत कराया कि एनपीए में लगातार वृद्धि बैंकर्स के लिए चिंता का विषय है क्योंकि यह बैंक की तरलता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। वर्तमान एन.पी.ए स्तर सितम्बर 2018 के रू 43982 करोड़ से बढ़कर सितम्बर 2019 में रु 53786 करोड़ तक पहुँच गया है जो कि 22% की कुल वृद्धि दर्शाता है। प्रदेश में कुल 10.70 लाख वसूली प्रमाण पत्र (RCs) तहसील स्तर पर वसूली हेतु लम्बित है जिनमें बैंकों की कुल रू 8959.91 करोड़ की धनराशि निहित है जिसमे से कुल रू 2547 करोड़ धनराशि के 3 लाख खाते एक वर्ष से अधिक अवधि से लम्बित है। सरफेसी एक्ट के अंतर्गत DM अनुमति हेतु लंबित खातों की निरंतर बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। गत एक वर्ष में इन लम्बित खातों में तिगुनी वृद्धि दर्ज करते हुए इनकी संख्या 1791 खाते (रू 823 करोड़) से बढ़कर 5194 खाते (रू 2086 करोड़) हो गई है।

(कार्यवाही: राजस्व परिषद एवं संस्थागत वित्त महानिदेशालय)

अंत में उन्होंने मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश; माननीय वित्त मंत्री, माननीय कृषि मंत्री, उत्तर प्रदेश व प्रदेश शासन के शीर्ष अधिकारियों तथा सभा में मौजूद सभी सदस्यों की सक्रिय भागीदारी एवं गरिमामयी उपस्थिति हेतु आभार व्यक्त किया।

श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी, आई.ए.एस., मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन ने अपने सम्बोधन में मुख्यत: राज्य व केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं पर प्रकाश डाला जिसके मुख्य बिन्दु निम्नवत है -

- प्रदेश सरकार द्वारा निवेश को आकर्षित करने हेतु आयोजित यू. पी. इन्वेस्टर समिट 2018 में रू. 4.28 लाख करोड़ के MoU हस्ताक्षरित किये गये थे जिसमें से रू. 1.28 लाख करोड़ धनराशि के प्रस्तावों पर कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है तथा बैंकों द्वारा वित्त पोषण भी सुनिश्चित किया जा रहा है।
- 40% से कम ऋण जमानुपात वाले जनपदों की संख्या गत तिमाही में 19 से घटकर 15 हो गयी है|
- वार्षिक ऋण योजना समय बद्ध तरीके से वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ही तैयार की जानी चाहिए ताकि अग्रिम वित्तीय वर्ष में इस पर कार्य करने हेतु बैंकों को पर्याप्त समय प्राप्त हो सके|

(कार्यवाही: समस्त अग्रणी बैंक / राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ0 प्र0)/ नाबार्ड)

- सेवा क्षेत्र की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए उन्होने कहा कि इस क्षेत्र में संभावनाओं के नए आयाम खुले हैं| इस में अभी तक मात्र 19% निवेश संभव हो सका है| क्षेत्र में योगदान बढाने हेतु केन्द्र/ राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं विशेष रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना, शिक्षा ऋण व नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। **(कार्यवाही: आवास एवं शहरी नियोजन विभाग/ समस्त बैंक)**
- बैंकों द्वारा विभिन्न सरकार प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का समय बद्ध तरीके से निस्तारण किया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए|
- प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना "एक जनपद एक उत्पाद" के अंतर्गत यदि बैंकों द्वारा अधिकाधिक लघु एवं परंपरागत उत्पादों के उद्यमियों को वित्त पोषित किया जाता है तो इससे निश्चय ही वार्षिक ऋण योजनांतर्गत लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोग प्राप्त होगा|

सभी का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने बैंकों से अनुरोध किया कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक के अतिरिक्त भी विभिन्न स्तरों पर आयोजित बैठकों में सरकार द्वारा विभिन्न प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा की जाए ताकि प्रदेश के विकास को बेहतर गति से आगे बढ़ाया जा सके|

श्री सूर्य प्रताप शाही जी, माननीय कृषि मंत्री, उत्तर प्रदेश ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय वित्त मंत्री का अभिवादन करते हुए सभा में उपस्थित समस्त अधिकारियों को उनकी सक्रिय भागीदारी हेतु धन्यवाद दिया व निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला:

- प्रदेश के विकास दर को 10% से बढाने हेतु राज्य के प्रत्येक क्षेत्र में पूंजी निवेश बढाए जाने की आवश्यकता है|
- प्रदेश में कृषि क्षेत्र में भी गत वर्षों में एक अच्छा प्रयास किया गया है जिसके परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्र में विकास दर की गति 2015-16 में 5.6 % से बढकर वर्तमान में 7.2% तक पहुंच गई है जो देश के औसत से दुगनी गति परिलक्षित करता है।
- प्रदेश के ऋण जमानुपात में वृद्धि लाने हेतु समस्त बैंकों द्वारा समन्वित प्रयास की आवश्यकता है। हमारे राज्य के 15 जनपद जिनका में ऋण जमा अनुपात 40% से कम है जिनमें से 3 जनपद यथा सिद्धार्थ नगर, फतेहपुर तथा चंदौली सम्भावनाशील जनपद हैं जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के है। पूर्वी व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में व्याप्त आर्थिक विषमता पर ध्यान देते हुए ऋण जमानुपात की दृष्टि से आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

  (कार्यवाही: समस्त बैंक/ सम्बन्धित विभाग)
- आज के डिजिटलीकरण के परिदृश्य में समस्त किसानों को डीबीटी के माध्यम से ही विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है जिससे भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में सहायता मिल रही है।
- कृषि संबंधित विभिन्न सरकार प्रायोजित अनुदान योजनाओं के अंतर्गत बैंकों में लंबित आवेदन पत्रों में शीघ्र निस्तारण की प्रक्रिया संपन्न कराई जाए ताकि कृषकों को अनुदान का लाभ सही समय से प्राप्त हो सके।

  (कार्यवाही: समस्त बैंक/ सम्बन्धित विभाग)
- वार्षिक ऋण योजनान्तर्गत आवंटित लक्ष्यों को इस वित्तीय वर्ष के अंत तक पूर्ण किए जाने हेतु अग्रिम प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

  (कार्यवाही: समस्त बैंक)

श्री सुरेश खन्ना जी, माननीय वित्त मंत्री, उत्तर प्रदेश ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय कृषि मंत्री का अभिवादन करते हुए सभा में उपस्थित अन्य अधिकारीगणों को प्रदेश के विकास में बैंकों की महती भूमिका पर प्रकाश डालते हुए समस्त को निम्न बिन्दुओं से अवगत कराया:

- प्रदेश की फसल ऋण मोचन योजना को बैंकों के सहयोग से अत्यंत सफलतापूर्वक संपन्न किया गया।
- पूर्वांचल एवं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में भी बैंकों द्वारा अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जा रहा है।
- छोटे तथा सीमांत किसानों पर विशेष ध्यान देते हुए कृषि ऋण एवं उर्वरकों की सुलभ उपलब्धता, सिंचाई तथा विपणन उपलब्धता आदि की ओर विषेष ध्यान दिया जा रहा है।
- एमएसएमई सेक्टर प्रदेश में औद्योगिक विकास और रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में एक सशक्त माध्यम है तथा इसमें विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना " एक जनपद एक उत्पाद" के अंतर्गत बैंकों द्वारा अधिक से अधिक वित्त पोषण की आवश्यकता है।

- कृषि प्रधान प्रदेश की व्यापक आवश्यकताओं को देखते हुए वर्तमान वर्ष में पर्याप्त व्यय का प्रावधान है। राज्य सरकार किसानों के कल्याण एवं उनके आर्थिक समृद्धि के लिए कृत संकल्पित है। किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुनी किए जाने के संकल्प की पूर्ति हेतु कृषि, उद्यम, पशुपालन, मत्स्य पालन, डेरी, आदि को प्रोत्साहित करते हुए किसानों की समृद्धि के उद्देश्य से कृषि उत्पादन में वृद्धि की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

- प्रदेश के ऋण जमा अनुपात (C:D Ratio) को राष्ट्रीय औसत तक पहुँचाने हेतु अपार संभावनाएं मौजूद हैं जिनके बेहतर प्रबन्धन की आवश्यकता है। प्रदेश में व्याप्त छोटे उद्योग प्रदेश की अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। अतः बैंकों को छोटे उद्योगों तक अपनी सुविधाओं को सुगमतापूर्वक पहुंचाया जाना चाहिए।

अंत में उन्होंने सभी स्टेकहोल्डर्स को समंवित रूप से प्रदेश के ऋण जमा अनुपात को अखिल भारतीय स्तर पर लाने हेतु प्रयास करने का आह्वाहन किया ताकि देश की विकास गाथा में हमारा प्रदेश अहम भूमिका का निर्वहन कर सके।

श्री अनिल कुमार शर्मा जी, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय कृषि मंत्री व वित्त मंत्री तथा हुए सभा में उपस्थित अन्य अधिकारीगणों का अभिवादन करते हुए निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला:-

- उन्होंने सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए समस्त को अवगत कराया कि वित्तीय समावेशन व साक्षरता के विषय को कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप करीब 65 लाख विद्यार्थियों को इसका लाभ प्राप्त हो रहा है।
- प्रदेश के 2 जनपदों यथा लखीमपुर खीरी एवं अयोध्या को वित्तीय साक्षरता के केंद्र हेतु चिन्हित किया गया है तथा इन दोनों जनपदों में अच्छा कार्य किया जा रहा है।
- भारतीय रिजर्व बैंक के डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश के 2 जनपदों यथा सिद्धार्थ नगर एवं फिरोजाबाद को एक वर्ष के भीतर पूर्ण रूप से डिजीटल बनाने हेतु चयनित किया गया है।
- अधिकाधिक लघु एवं सीमांत किसानों को बैंकों के साथ जोड़े जाने का प्रयास किये जाने के साथ ही राज्य सरकार द्वारा विभिन्न सरकार प्रायोजित व कृषि विशेष योजनाओं की टेलीविजन, रेडियो आदि के माध्यम से जागरूकता उत्पन्न की जाय।
- उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित भूमि लगभग 78% है जिसमें से लगभग 81% भूमि की सिंचाई ट्यूब वेल्स के माध्यम से की जा रही है| अतः राज्य सरकार का प्रयास होना चाहिए कि किसानों को सिंचाई हेतु अन्य माध्यमों यथा तालाब चेक डैम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग आदि हेतु प्रेरित किया जाए ताकि भविष्य में ग्राउंड वाटर लेवल की समस्या से प्रदेश को जूझना ना पड़े|
- एमएसएमई के लक्ष्यों की उपलब्धि हेतु उन्होंने समस्त बैंकों की सराहना की।

- उत्तर प्रदेश में कार्यरत 75 RSETIs में गत वर्ष लगभग 52000 प्रशिक्षणार्थीयों को ट्रेनिंग दी गई है जबकि मात्र 31% को ही बैंकों द्वारा ऋण प्रदान किया गया है। अतः बैंकों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक लोगों को ऋण प्रदान करने का प्रयास करें।

(कार्यवाही: समस्त बैंक/ ग्राम विकास विभाग/ निदेशक, कौशल विकास मिशन)

- मार्च 2019 की सूचना के अनुसार बैंकों की रिकवरी 65% रही है। प्रदेश सरकार से अनुरोध है कि इस दिशा में आवश्यक दिशानिर्देश जारी करने का कष्ट करें ताकि शेष धनराशि को पुनः ऋण के रूप में प्रदान कर इसे अर्थव्यवस्था में समाहित किया जा सके।
- बैंकों का प्रयास होना चाहिए कि प्रत्येक प्रधानमंत्री जनधन खाते को कम से कम एक जनसुरक्षा योजना से जोड़ा जाए। **(कार्यवाही: समस्त बैंक)**
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कृषि क्षेत्र में क्रेडिट बढ़ाने हेतु वर्किंग ग्रुप का गठन किया गया था जिसके अंतर्गत रिकमेंडेशंस प्राप्त की जा चुकी है व शीघ्र ही इस क्रियांवित किया जाएगा।
- RBI ने MSME क्षेत्र के आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के कारणों की पहचान करने और दीर्घकालिक समाधान के प्रस्ताव हेतु SEBI के पूर्व अध्यक्ष, श्री यू के सिन्हा की अध्यक्षता में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर एक Expert Committee का गठन किया है।

श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश नें अपने सम्बोधन में माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी, उत्तर प्रदेश; मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन; कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक; कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा; समस्त बैंकर्स, विभागीय अधिकारी गण को प्रदेश के विकास को दिशा प्रदान करने हेतु आभार व्यकत किया व राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ0 प्र0) की बैठक को सुनियोजित तरीके से आयोजित करने हेतु सभी हितधारकों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए प्रदेश में की जा रही विभिन्न विकास गतिविधियों से अवगत कराया:-

- माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था को 2024 तक 5 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचाने का वृहद लक्ष्य रखा गया है जिसके अंतर्गत देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा 1 बिलियन यूएस डॉलर का योगदान देने हेतु प्रयास प्रारंभ किए जा रहे हैं लेकिन इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु हरे क्षेत्र को एक सकारात्मक और विकासोन्मुख माहौल देने की आवश्यकता है और इसमें वित्तीय संस्थानों एवं बैंकों की महती भूमिका है।
- इसी क्रम में उन्होंने 8 अगस्त 2019 को एक लाख किसान क्रेडिट कार्ड की लॉन्चिंग पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए आज की बैठक में 1.51 लाख किसान क्रेडिट कार्ड की लॉन्चिंग करने पर समस्त बैंकों को बधाई दी व इस प्रयास के लिए सभी का अभिनंदन किया। साथ ही समस्त बैंकों से अनुरोध किया कि व्यापक स्तर पर क्रेडिट कैंपों का आयोजन कर प्रत्येक पात्र और इच्छुक कृषक को इस वित्तीय वर्ष के अंत तक किसान क्रेडिट कार्ड से आच्छादित करने हेतु सघन प्रयास किये जाएं।

- स्वयं सहायता समूह विशेषकर महिला स्वयं सहायता समूह को वित्त पोषित कर उन्हें वित्तीय रूप से सक्षम बनाने में बैंकों द्वारा एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया जाता है और हर्ष का विषय है कि आज कई स्वयं सहायता समूहों की विकास गाथा को संकलित कर तैयार की गई एक पुस्तिका का विमोचन आज की बैठक में किया गया|

- माननीय प्रधानमंत्री की संकल्पना को पूर्ण करने हेतु बैंकों का आह्वाहन किया। मुझे प्रसन्नता है कि इसी क्रम में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जनपद सिद्धार्थनगर जो कि एक महत्वाकांक्षी जनपद भी है व जनपद फिरोज़ाबाद को 1 वर्ष के भीतर संपूर्ण रूप से डिजिटल करने हेतु चयनित किया गया है|

- राज्य सरकार ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य को गति दिए जाने के उद्देश्य से बैंकों को कंसोर्सियम के माध्यम से 7000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को हाल ही में स्वीकृति दी है| जिन बैंकों का ऋण जमानुपात कम है वे राज्य सरकार द्वारा अवस्थापना विकास हेतु किए जाने वाले प्रयासों में अपना सक्रिय योगदान दे सकते हैं|

- राज्य सरकार ने विभिन्न जनपदों के विशिष्ट व परंपरागत उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु एक जनपद एक उत्पाद योजना प्रारंभ की है और इस योजना के बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं| प्रदेश में होने वाले निर्यात में 28% की वृद्धि हुई है तथा मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश देश के 3 सबसे बड़े अग्रणी निर्यातक राज्यों में से एक होगा|

- यद्यपि प्रधानमंत्री मुद्रा योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में नवम्बर तक 201929 लाख लाभार्थियों को ऋण प्रदान किया गया है ,तथापि प्रदेश में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को आसान शर्तों पर ऋण प्रदान करने की अपार सम्भावनाएं निहित हैं। स्टैंड अप इंडिया योजना अंतर्गत हमारा प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है परंतु 30 सितंबर 2019 तक मात्र 1045 लाभार्थियों को ही इस योजना के अंतर्गत ऋण प्रदान किए गए हैं जो मौजूदा सम्भावनाओं के सापेक्ष अपेक्षाकृत कम है|

- वर्तमान में प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में हमारा प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है| प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत प्रदेश में 14.53 लाख आवासों की स्वीकृति के सापेक्ष 8.93 लाख आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है तथा शेष कार्य प्रगति पर है| प्रदेश में क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत बैंकों द्वारा 60004 प्रस्तावों में 314 करोड़ की धनराशि का वितरण किया गया है| उन्होंने आग्रह किया कि बैंक, केंद्र एवं राज्य सरकार "सबके लिए आवास" मिशन को निर्धारित समय सीमा में युद्ध स्तर पर पूर्ण करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(कार्यवाही: शहरी एवं नियोजन विभाग/ ग्राम विकास विभाग/ समस्त बैंक)

- उत्तर प्रदेश निवेश के नए आकर्षक गंतव्य के रूप में उभरा है इससे प्रदेश में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे राज्य सरकार स्थापना सुविधाओं को बेहतर करने हेतु कृत संकल्पित है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की योजनाएं निर्माणाधीन है मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेस वे योजना के निर्माण की दिशा में हमारी कार्यवाही तेजी से प्रगतिशील है साथ ही राज्य सरकार ने इंटरनेट कनेक्टिविटी डिस्टिक हेड क्वार्टर को फोरलेन कनेक्टिविटी से जोड़ने की कार्यवाही अपने स्तर पर प्रारंभ की है। भारत का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड नेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के अंदर नोएडा के पास जेवर में कार्य प्रारंभ होने जा रहा है| जेवर एयरपोर्ट प्रदेश की एक बड़ी उपलब्धि होगी। डिफेंस कॉरिडोर के तहत छः नोड्स चित्रकूट, झांसी, कानपुर, आगरा अलीगढ़

और लखनऊ चिन्हित किए गए हैं। साथी अन्य जनपदों में निवेश आकर्षित करने हेतु संबंधित निवेशकों से एक संवाद प्रारंभ हुआ है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में लगभग 20 हजार करोड़ का निवेश संभावित है। इसी को ध्यान में रखते हुए माह फरवरी में लखनऊ में डिफेंस एक्सपो आयोजित किया जा रहा है।

➢ प्रदेश सरकार ने वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, विंध्यवासिनी धाम, चित्रकूट, देवीपटन एवं अन्य ऐसे सभी क्षेत्रों को चिन्हित करके स्पिरिचुअल टूरिज्म के साथ साथ इको टूरोज़म, वाइल्डलाइफ टूरोज़म, हेरिटेज टूरिज्म एवं अन्य सभी प्रकार की पर्यटन की संभावनाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक नया प्रयास प्रारंभ किया है। राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में रोज़गार सृजन हेतु प्रशिक्षण का अभियान भी प्रारंभ किया गया है।

➢ राज्य सरकार द्वारा बुंदेलखंड एवं विंध्य क्षेत्र में पेयजल की "हर घर नल" योजना का शुभारम्भ किया जा रहा है।

➢ प्रदेश के ऋण जमानुपात को राष्ट्रीय स्तरतक पहुँचाने हेतु सघन प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया।

➢ उन्होंने सभा को अवगत कराया कि जमीनी स्तर पर बेरोज़गार लोगों को ऋण के माध्यम से रोज़गार के अवसर प्रदान करने में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सभी हितधारकों द्वारा समंवित प्रयास करते हुए ऋण शिविर ,रोज़गार मेलों का आयोजन किया जाना चाहिए जिससे अधिक से अधिक लोगों को व्यवसाय प्रदान करते हुए प्रदेश के विकास में सभी की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

(कार्यवाही: समस्त बैंक/ सम्बन्धित विभाग)

➢ राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने वाली 15 ऐसी सेवाओं का चुनाव किया गया जैसे पेंटर,कारपेंटर , राजमिस्त्री, नाउ, मोची आदि को विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के माध्यम से कम पूंजी में मैं ऋण उपलब्ध कराया गया है | ऋण सुविधा आसानी से उपलब्ध ना होने की स्थित में अक्सर चिटफंड कंपनियां लोगों का फायदा उठाती हैं वह कई मामलों में यह भी पाया गया है की कंपनिया उनके साथ धोखा भी करती है |वर्तमान में कई चिटफंड कंपनियां सक्रीय हुई है और उन पर शिकंजा कसे जाने की आवश्यकता है।

(कार्यवाही: भारतीय रिज़र्व बैंक/ संस्थागत वित्त विभाग)

➢ यह प्रसन्नता का विषय है कि वर्तमान में प्रदेश के समस्त केन्द्रों पर 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर कम से कम एक बैंकिंग आउटलेट (बैंक शाखा/ बैंक मित्र/ए.टी.एम./इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक) के माध्यम से बैंकिंग सुविधाए प्रदान की जा रही है।

➢ प्रदेश में 23 नवंबर को बैंकों की सुरक्षा से संबंधित एक बैठक का आयोजन किया गया था । ऐसा पाया गया है कि पिछले 6 माह के दौरान 4 बैंकों में डकैती का मामला सामने आया है जिनमें तीन बैंक शाखाएं आईसीआईसीआई बैंक की तथा एक आईडीएफसी बैंक की है, इन शाखाओं में सीसीटीवी कैमरा खराब पाए गए साथ ही सुरक्षा का समुचित इंतजाम नहीं पाया गया| सभी बैंकों द्वारा शाखाओं में सीसीटीवी कैमरास की सुरक्षा व उसकी रिकॉर्डिंग की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए| कम से कम प्रत्येक तिमाही में एक बार डीएलसीसी की बैठक का आयोजन किया जाना चाहिए जिससे बैंकों को सुरक्षा की दृष्टि से आने वाली समस्याओं व जनपद स्तरीय अन्य समस्याओं पर भी विचार विमर्श किया जा सके।

(कार्यवाही: भारतीय रिज़र्व बैंक/ संस्थागत वित्त विभाग/ समस्त बैंक)

➢ जिन बैंकों का ऋण जमा अनुपात प्रदेश के ऋण जमा अनुपात से कम है उन्हें इस दिशा में ध्यान देने की आवश्यकता है |

- मानननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा बाणसागर योजना का लोकार्पण किया गया है जिसके अंतर्गत अब तक डेढ़ लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जा चुका है। वर्तमान में राज्य सरकार सरयू नहर परियोजना को, मध्य गंगा नहर परियोजना को और अर्जुन सहायक परियोजना जैसी लगभग एक दर्जन सिंचाई की ऐसी परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है जो हमारे सिंचन की क्षमता को इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 20 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाएगी। साथ ही इस क्षमता को ड्रिप इरिगेशन के साथ जोड़ने की दिशा में भी प्रयास शुरू किए गए हैं। इन प्रयासों के तहत राज्य सरकार द्वारा किसानों को सब्सिडी प्रदान की जा रही है और यदि इस दिशा में बैंकों द्वारा ऋण प्रदान कर किसानों को प्रोत्साहित किया जाए तो लागत कम और उत्पादक क्षमता ज्यादा प्राप्त हो सकते हैं।

(कार्यवाही: समस्त बैंक)

- राज्य सरकार द्वारा नाबार्ड के साथ मिलकर 362 FPOs का सम्मेलन संपन्न किया गया है । इस सम्मेलन में प्रत्येक क्षेत्र से जुड़े हुए एफपीओ द्वारा सहभागिता की गयी |एफपीओ किसानों की आय में वृद्धि करने के साथ साथ राज्य की अर्थव्यवस्था को सुधारने में निश्चय ही सहयोग प्राप्त होगा। उन्होंने कृषि विभाग एवं नाबार्ड से प्रदेश के सभी ग्राम पंचायत में एफपीओ का गठन करने हेतु प्रयास करने का आह्वाहन किया।

(कार्यवाही: कृषि विभाग/ नाबार्ड/ समस्त बैंक)

- उन्होंने कहा कि मेरा विश्वास है यदि बैंक द्वारा वृहद स्तर पर क्रेडिट कैंपों का आयोजन कर लोगों से सीधा संवाद स्थापित किया जाएगा वह उन्हें ऋण हेतु उत्साहित किया जाएगा तो निश्चय ही 1 वर्ष के भीतर ही ऋण जमा अनुपात को नेशनल एवरेज से ऊपर पहुंचाया जा सकता है।

(कार्यवाही: समस्त बैंक/ सम्बन्धित विभाग)

- उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा को बुंदेलखंड एक्सप्रेस में में रूचि हेतु धन्यवाद दिया और साथ ही समस्त बैंकों को प्रदेश में अवस्थापना परियोजनाओं में निवेश करने हेतु आमंत्रित किया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को भी राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है जिससे गोरखपुर और बलिया जनपद से उसे जोड़ा जाएगा। इसके अतिरिक्त गंगा एक्सप्रेसवे जो कि लगभग 640 किलोमीटर लम्बा मेरठ से प्रयागराज को जोड़ेगा।

- उन्होंने उपस्थित सभी लोगो का अभिवादन करते हुए कहा कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकों के माध्यम से राज्य की कार्य योजना के निर्माण में सहयोग मिलता है साथ ही राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने हेतु कदम उठाने में भी सहायता मिलती है| मेरा विश्वास है कि राज्य सरकार और बैंक साथ मिलकर कार्य करते हुए माननीय प्रधानमंत्री के 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनामी के स्वप्न को पूर्ण करने में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े प्रदेश की भूमिका में रहने हेतु 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर का योगदान देने में अवश्य समर्थ होंगे।

बैठक के अंत में श्री बी.एस. लुथरा, उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री, श्री सुरेश खन्ना, माननीय वित्त मंत्री, उत्तर प्रदेश एवं श्री सूर्य प्रताप शाही, माननीय कृषि मंत्री, उत्तर प्रदेश को विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हुए सभी राज्य तथा केंद्र सरकार के समस्त अधिकारीगणो, बैंकर्स के साथ साथ समस्त उपस्थित जनों का आभार व्यक्त किया जिसके सहयोग से राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक संपन्न की जा सकी |

.... ****** ....

List of the participants for SLBC (UP) Meeting dated 30.12.2019

PARTICIPATION SHEET

Sr. No.	Organization	Designated Member	Status of Participation	Participating Authority & Contact Details			Email_ID
				Designation	Name	Contact No.	
1	Govt. of U.P.	Chief Minister. Uttar Pradesh	Yes	Chief Minister	Shri Yogi Adityanath Ji		
2	Govt. of U.P.	Finance Minister	Yes	Finance Minister	Shri Suresh Khanna		
3	Govt. of U.P.	Agriculture Minister	Yes	Agriculture Minister	Shri Surya Pratap Sahi	9415022598	
4	Bank of Baroda, Corporate Office, Mumbai	Chairman & Managing Director / Executive Director	Yes	Executive Director	Shri Vikramaditya Singh Khichi		
5	Bank of Baroda, Lucknow Zone	General Manager	Yes	General Manager	Dr. Ram Jass Yadav	7379573333	zm.upu@bankofbaroda.com
6	Reserve Bank of India, Lucknow	Executive Director	Yes	Executive Director	Shri Anil Kumar Sharma	8424019304	aksharma@rbi.org.in
7		Regional Director	Yes	Regional Director	Shri R Lakshmi Kanth Rao	9094028645	rlkrao@rbi.org.in
8				General Manager	Shri R P Singh	9827577580	rpsingh@rbi.org.in
9	NABARD, R.O., Lucknow	Chief Gen. Manager	No	General Manager	Shri J S Upadhyay	9967398630	js.upadhyay@nabard.org
10	State Bank of India	Chief Gen. Manager/Gen. Manager	Yes	Chief General Manager	Smt. Saloni Narayan	7738248300	cgm.lholuc@sbi.co.in
11				General Manager	Shri G S Rana	7506094873	gm3.lholuc@sbi.co.in
12	Allahabad Bank, Lucknow	Field Gen. Manager/ State Head	Yes	General Manager	Shri Ravindra Singh	9815742224	fgmo.luc@allahabadbank.in
13	Union Bank of India, Lucknow	Gen. Manager/ State Head	Yes	General Manager	Shri Atul Kumar	9886300111	atulkumar@unionbankofindia.com
14	Syndicate Bank	Field General Manager	Yes	Zonal Manager	Shri C Pulla Reddy	9535310880	cpullareddy24@gmail,com
15	Bank of India	Gen. Manager/ State Head	Yes	General Manager	Shri Brij Lal	0522-2721766	nb.north2@bankofindia.co.in
16	Central Bank of India	Field Gen. Manager/ State Head	Yes	General Manager	Shri Narendra Singh	9765552575	zm.luckzo@centralbank.co.in
17	Punjab National Bank	Field Gen. Manager/ State Head	Yes	General Manager	Shri Sameer Bajpai	7060081975	sbajpai@pnb.co.in
18	Canara Bank	Chief Gen. Manager/ State Head	Yes	General Manager	Shri U K Sharma	9473527060	umeshkumarsharma@canarabank.com
19	Indian Bank	Dy. Gen. Manager/ State Head	Yes	Zonal Manager	Shri N Anand Kumar	9432013447	anandkumar30701@indianbank.co.in
20	Corporation Bank	Dy. Gen. Manager/ State Head	Yes	Zonal Head	Shri Gyana Ranjan Sarangi	9845416052	sarangi.gyana@coorbank.co.in
21	Andhra Bank	Dy. General Manager/ State Head	Yes	Zonal Manager	Shri G Shankarlal	8019711802	gslal@andhrabank.co.in
22	Indian Overseas Bank	Chief Regional Manager/State Head	No	Asstt. Gen. Manager	Shri R Rangrajan	9305499717	rrajan@iobnet.co.in
23	Oriental Bank of Commerce	Zonal Head	Yes	Dy. General Manager	Shri Sudhanshu Shekhar Das	8051807700	co.lko@obc.co.in
24	United Bank of India	Chief Regional Manager	Yes	Dy. General Manager	Shri Vittesh Kumar	7956098590	crmlko@unitedbank.co.in
25	UCO Bank	Zonal Head	Yes	Zonal Manager	Shri Om P Verma	8450050001	zo.lucknow@ucobank.co.in
26	Bank of Maharashtra	State Head	Yes	Zonal Head	Shri G D Singh	8872253136	zmlucknow@mahabank.co.in
27				Senior Manager	Shri Sudhakar Tiwari	9458234543	crcagr.lic@mahabank.co.in
28	Punjab & Sind Bank	Zonal Head	No	Asstt. Gen. Manager	Shri Rahul Sawant	9650399295	zo.lucknow@psb.co.in
29	Baroda U.P. Gramin Bank	Chairman	No	General Manager	Shri Jitendra Kumar	8013523254	jitendra.kumar@bankofbaroda.co.in
30	Purvanchal Bank	Chairman	No	General Manager	Shri Ashok Mishra	7571812301	a_mishra@sbi.co.in
31	Prathma U P GraminBank	Chairman	Yes	Chairman	Shri Anil Kumar Sharma	8130167878	cms@pparathamaupbank.com
32	Aryavart Bank	Chairman	Yes	Chairman	Shri S B Singh	9594718299	shiv.singh2@bankofindia.co.in
33	Kashi Gomti Samyut Gramin Bank	Chairman	No	General Manager	Shri Rajeev Srivastava	9984970001	gmkgsg@kgsgbank.co.in
34	Axis Bank	Circle Head	Yes	Circle Head	Shri Madhudeep Rai	9920564244	madhudeep.rai@axisbank.com
35	HDFC Bank, Lucknow	Zonal Head	Yes	Cluster.Head	Shri Bakul Sikka	9305555550	bakul.sikka@hdfcbank.com
36	ICICI Bank, Lucknow	Zonal Head	Yes	Zonal Head	Shri Amitabh Singh	9771423717	amitabh.singh@icicibank.com

Sr. No.	Organization	Designated Member	Status of Participation	Participating Authority & Contact Details			Email_ID
				Designation	Name	Contact No.	
37	IDBI Bank Ltd	Zonal Head	Yes	General Manager	Shri Sameer Bajaj	8419934433	s-bajaj@idbi.co.in
38	India Payment Post Bank	Director	No	Zonal Head	Shri Avinash Sinha	7752085558	avinash.ks@ippbonline.co.in
39	Govt. of U.P.	Chief Secretary	Yes	Chief Secretary	Shri Rajendra Kumar Tiwari, IAS		
40	Govt. of U.P.	PS to Hon'ble Chief Minister	Yes	Principal Secretary	Shri S P Goyal, IAS		
41	Finance	Addl. Chief Secretary	Yes	Addl. Chief Secretary	Shri Sanjeev Kumar Mittal, IAS		
42	Home	Addl. Chief Secretary	Yes	ACS & CEO UPEIDA	Shri Avnish Awasthi, IAS	9871115034	
43	Planning Department	Addl. Chief Secretary	Yes	Addl. Chief Secretary	Shri Kumar Kamlesh		
44	Agriculture	Principal Secretary	Yes	Principal Secretary	Shri Amit Mohan Prasad, IAS		
45	Rural Development	Principal Secretary	Yes	Principal Secretary	Shri Anurag Srivastava, IAS		
46	Cooperative	Principal Secretary	Yes	Principal Secretary	Shri M V S Rami Reddy, IAS	9415105000	
47	Dairy Development	Principal Secretary	Yes	Principal Secretary	Shri B L Meena, IAS		
48	Board of Revenue	Commissioner & Secretary, GoUP	Yes	Commissioner & Secretary	Shri Rajnish Gupta, IAS		
49	SIDBI	State Head/General Manager	No	Dy, General Manager	Shri Heera Lal Srivastava	9811201401	hlsrivastava@sidbi.in
50	Rural Development	Commissioner	Yes	Commissioner	Shri K Ravindra Naik, IAS	8953661111	crd-up@nic.in
51	Social Welfare	Principal Secretary	No	Special Secretary	Shri Dheeraj Kumar, IAS	9198699900	
52	MSME & Export Promotion	Principal Secretary	No	Joint Director	Shri Sunil Kumar	9415458772	odoopcell@gmail.com
53	MSME	Director	No	Special Secretary	Shri Pradeep Kumar	9415070122	specialsecretarymsme@gmail.com
54	CM Office			Review Officer	Shri Vijay Prakash Tiwari	7619960220	smartie.vijay.123@gmail.com
55	UPSGVB	Managing Director	Yes	Addl. Reg. (Coop. Banking) & MD-LDB	Shri Vamsi Andre		andravamsi1985@gmail.com
56	U P Cooperative Bank	Managing Director	Yes	Managing Director	Shri Bhupendra Kumar	9412635609	
57	Directorate of Instt. Finance (DIF)	Director General	Yes	Director General	Shri Shiv Singh Yadav	9415106200	
58				Joint Director	Shri Atul Kumar Chauhan	9412206788	
59				Dy. Director	Shri Shiv Shankar	9935069749	shivshankar.dif@gmail.com
60				Reserch Officer	Dr. Raghuvendra	9415654000	
61	Directorate of Agriculture	Director	Yes	Director Agriculture	Shri Soraj Singh	8429031506	dirag@nic.in
62			Yes	Director Agri. Stat, UP	Shri V K Singh	9415093148	agristatup@gmail.com
63	KVIB	Chief Executive Officer	No	Dy. CEO	Shri Hari Ram Singh	7408410716	upkvib-pmegp@gmail.com
64	UIDAI	Asstt. Director General	Yes	Asstt. Director General	Shri Vivek Kumar Daksh	9415331333	vivek.daksh@uidai.net.in
65	BSNL, UP (East) Circle	General Manager	Yes	General Manager	Shri Rana Ashok Kumar Singh	9454011011	sarsijsaurabh@bsnl.co.in
66	HUDCO	General Manager	Yes	General Manager	Shri Rahul Ji Srivastava	8004923416	rahulji.srivastava@gmail.com
67	Bank of Baroda			Dy. General Manager	Shri B S Luthara	0522-6677722	slbc.up@bankofbaroda.com
68				Senior Manager	Shri Brijesh Kumar Gupta	0522-6677730	slbc.up@bankofbaroda.com
69				Manager	Shri Ritesh Rai	0522-6677717	slbc.up@bankofbaroda.com
70				Manager	Shri Ajit Kumar	0522-6677694	slbc.up@bankofbaroda.com
71				Officer	Ms Anjali Singh	0522-6677694	slbc.up@bankofbaroda.com
72				Officer	Ms. Shikha Tripathi	0522-6677726	slbc.up@bankofbaroda.com
73				Business Associates	Shri Arun Kumar Agarwal	0522-6677725	slbc.up@bankofbaroda.com